मिटीगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपॉवर)

परियोजना का परिचय

राज्य सरकार द्वारा जोधपुर संभाग के छः जिलों में अन्तराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) की सहायता से पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना, (Mitigating poverty in western Rajasthan) **MPOWER** परियोजना स्वीकृत की गई है । राज्य के जोधपुर संभाग के बायतु (बाडमेर), सांकडा (जैसलमेर), बाप (जोधपुर), सांचोर (जालोर), बाली (पाली) तथा आबू रोड (सिरोही) पंचायत समितियों में यह परियोजना संचालित की जा रही है। इन पंचायत समितियों में राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किये गये गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले शत–प्रतिशत बीपीएल परिवार परियोजना के लक्षित समूह होंगे। परियोजना की प्रस्तावित अवधि छः वर्ष है। इस परियोजना से 245 ग्राम पंचायतों के 1040 ग्रामों के लगभग एक लाख परिवारों को सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

परियोजना लागत

परियोजना की लागत 415 करोड़ रूपये हैं जिसमें आईफेड का 124 करोड़ रूपये, राज्य सरकार का 87.50 करोड़ रूपये, लाभान्वितों का अंशदान 10.50 करोड़ रूपये, बैंकों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को ऋण के रूप में 180 करोड़ रूपये एवं सर रतन टाटा ट्रस्ट से अनुदान के रूप में 13 करोड़ रूपये सम्मिलित हैं।

परियोजना का मूल उद्देश्य

गरीब परिवारों के स्थाई आजीविका के अवसरों का सृजन करना ताकि गरीब परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके। इस परियोजना के विशिष्ठ उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

अ. अकाल की सम्भावनाओं को कम करना एंव जल सुरक्षा मुहैया करना।

ब. आय में वृद्धि एवं रोजगार सृजन।

स. बाजार की आवश्यकतानुसार उत्पादकता में सुधार।

द. उत्पादकों की उनके उत्पादनों के उचित मूल्य प्राप्ति हेतु बाजार तक पहुंच तथा इस हेतु

Backward एवं Forward Linkages की स्थापना।

य. महिलाओं पिछड़ों एवं निराश्रितजनों को मुख्य धारा में लाने हेतु उनका सशक्तिकरण करना।

र. राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध राशि का उपयोग परियोजना से समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित कर सुनिश्चित करना।

इस योजनान्तर्गत आजीविका गतिविधियों के साथ–साथ सामुदायिक आधारभूत विकास (Infrastructure Development) कार्य हेतु रूपये 104 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसका उपयोग सूखे के प्रभाव को कम करने, प्रचलित आजीविका कौशल को संरक्षित करने एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से मेंड बंदी, खेत तलाई, मृदा सुधार हेतु गतिविधियां, उधानिकी, कुओं का निर्माण, चारागाह विकास, चारे के प्रसंस्करण एवं भण्डारण तथा उत्पादकता एवं विपणन व्यवस्था हेतु सी.एफसी. (Common Facility Centre) निर्माण आदि कार्यों हेतु किया जावेगा।

परियोजनान्तर्गत विशिष्ट नवाचार

अ. परियोजना के संसाधनों से प्रेरक राशि उपलब्ध कराने के साथ– साथ क्षेत्र में क्रियान्वित होने वाली अन्य सरकारी योजनाओं विशेष रूप से राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के साथ सामंजस्य (Convergence) स्थापित कर उपलब्ध कोष एवं कार्यों को डोवटेल किया जावेगा, जिससे परियोजना संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि सम्भव होगी।

ब. परियोजना के दौरान गांव के सभी वर्गों में समानता के मुद्दों को महत्व दिया जाएगा।

स. स्वयं सहायता समूहों को क्रय–विक्रय समूहों में (मार्केटिंग ग्रुप्स) विकसित कर उन समूहों को लघु उद्यमी के रूप में विकसित किया जावेगा। इस प्रकार परियोजना क्षेत्र में सामाजिक सशक्तिकरण को आर्थिक सुदृढ़ीकरण में परिवर्तित किया जाएगा।

परियोजना की उपलब्धियां

- बैस लाईन सर्वे किया जा चुका है।
- सभी ब्लॉक में RIM सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

संचालन समितियां

- राज्य परियोजना संचालन समिति] (SPSC) परियोजना संचालन समिति (PSC) एवं जिला परियोजना संचालन समितियों (DPCC) का गठन किया जाकर नियमित बैठके करवाई जा रही है।
- परियोजना की वेबसाईट विकसित की जा चुकी है। (**www.mpowerraj.in**) तथा नियमित प्रविष्टियां दर्ज करवाई जा रही है।
- परियोजना कार्मिकों की दो दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण तथा **M&E** की कार्यशाला सम्पन्न करवाई जा चुकी है।
- सभी परियोजना प्रबन्धकों को हरिशचन्द्र माथुर प्रशिक्षण केन्द्र में राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान वितीय एवं लेखा नियमों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है।
- IFAD Procurement Guideline की जानकारी देने एवं वितीय प्रबन्धन हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला करवाई जा चुकी है।
- सूचना एव संचार प्रोद्योगिकी के तहत CMIS का कार्य परियोजना की सहभागी संस्था सर रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है।
- दिनांक 25.7.10 से 27.7.10 तक परियोजना की प्रारम्भिक कार्यशाला (Start-up Workshop) सम्पन्न करवाई जा चुकी है।
- कुल छः विकास खण्डों में 14 गैर सरकारी संगठनों का चयन हो चुका है एवं FNGOs द्वारा कार्मिकों का पदस्थापन भी किया जा चुका है। जैसलमेंर जिले के सांकडा विकास खण्ड में Project Facilitation Teem (PFT) पैटर्न पर कार्मिको का चयन कर कार्य प्रारम्भ करवाया जा चुका है तथा FNGO के माध्यम से 939 गांवों में एवं PFT के माध्यम से 101 गांवों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
- समुदायिक नियमावली विकसित की गई है ।
- वित्तीय नियमावली का प्रारूप तैयार कर राज्य परियोजना संचालन समिति (SPSC) मे रखा गया जिसे प्रशासनिक विभाग से विस्तुत समीक्षा हेतु ग्रामीण विकास विभाग मे भिजवाया जा चुका है तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा सुझाये गये सुझावो अनुसार संशोधन कर पुनः ग्रामीण विकास विभाग को भिजवाया जा चुका है ।
- राज्य परियोजना संचालन समिति (SPSC) की प्रथम बैठक का आयोजन 13.09.2010 को किया जा चुका है ।
- एमपॉवर परियोजना में चयनित गैर सरकारी संगठनो को महानरेगा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को परियोजना क्षेत्र में संचालित करने हेतु FNGO को कार्यक्रारी संस्था (Executive Agency) राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जा चुका है ।

बुनियादी सामुदायिक संस्थाओं का सशक्तिकरण

- दक्ष प्रशिक्षकों के दो समूहों का (Batches) प्रशिक्षण पूर्ण करवाया जा चुका है ।
- दिनांक 10–12 जून–2010 को FNGO के स्टाफ का तीन दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण सम्पन्न करवाया जा चुका है ।
- परियोजना क्षेत्र मे माह दिसम्बर–2010 तक कुल 1379 स्वंय सहायता समूहो का गठन किया जा कर उन्हे प्रशिक्षण करवाया जा रहा हैं तथा स्वंय सहायता समूह के सदस्यो को प्रबन्धन पर शैक्षणिक भ्रमण (Exposure visit) पर भी भेजा जा रहा है।
- PRA/PLA एवं ग्राम योजना (Village Planning) हेतु कुल 6 (Batches) का प्रशिक्षण करवाया जा चुका है ।
- स्वंय सहायता समूह की अवधारणा पर परियोजना समन्वयक, टीम लीडर एवं CF के तीन (Batches) का प्रशिक्षण करवाया जा चुका है यह प्रशिक्षण SRTT की नोडल एजेन्सी CMF के माध्यम से करवाया गया है ।
- स्वंय सहायता समूह Modules (TOT) पर तीन Batch मे का प्रशिक्षण CFs को दिया जा चुका है ।
- स्वंय सहायता समूहों के लिये वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को बढावा देने के लिये एवं बैंकर्स की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु एक राज्य स्तरीय बैंकर्स कार्यशाला करवाई जा चुकी है ।
- आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्य प्रगति पर है।
- स्वंय सहायता समूहों के लिये वितीय सेवाओं की उपलब्धता को बढावा देने के लिये एवं उनकी साख को सुनिश्चित करने हेतु बैंकर्स के साथ वार्ता कर एक विकास खण्ड बाप हेतु यूकों बैंक एवं अन्य पांच विकास खण्डों हेतु स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के साथ शीघ्र ही अनुबन्ध किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- माह दिसम्बर 2010 तक 1379 स्वंय सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है तथा उनमें से 263 समूहों के खाते बैंक में खोले जाकर उन्हें बैंक से जोडा जा चुका है तथा शेष हेतु प्रयास जारी है।

आजीविका

- परियोजना क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों (Trade) के तहत सिलाई मशीन ऑपरेटर, स्पिनिंग ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड एवं कम्पयुटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिलवाये जाने हेतु माह दिसम्बर 2010 तक 258 युवाओं को प्रशिक्षण में भेजकर प्रशिक्षित किया गया है।
- कुल 123 युवाओं को प्रशिक्षण उपरान्त विभिन्न संस्थाओं मे नौकरी दिलवाई जा चुकी है।
- विभिन्न उत्पादों हेतु प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान करवाई जा रही है तथा RMOL मार्गदर्शिका अनुसार चयनित संस्थाओं में युवाओं को प्रशिक्षण करवाये जाने का कार्य प्रगति पर है तथा वितीय वर्ष 2010–11 की समाप्ति तक कुल 1200 युवाओं को प्रशिक्षित करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
- परियोजना क्षेत्र में कुल 33 फसल प्रदर्शन करवाकर किसानों की आजीविका बढ़ाने के प्रयास किय गये है।
- परियोजना क्षेत्र में कुल 60 पशु टीकाकरण कैम्प्स आयोजित किये जा चुके हैं।

सामुदायिक आधारभूत विकास कोष

- आजीविका कौशल को स्थिर करने एवं उत्पादकता मे वृद्धि करने हेतु परियोजना क्षेत्र के 330 गांवो की विकास योजना तैयार कर उनके 20 आजीविका आधारित सामुदायिक आधारभूत विकास गतिविधियां जिसमें चारागाह विकास एवं खडीन निर्माण आदि सम्मिलित है, की पहचान की जा चुकी है।
- व्यक्तिगत लाभ (केटेगरी–IV) के कार्यो की पहचान कर कुल 18 करोड रुपये के कार्य महानरेगा योजना के साथ कन्वर्जेन्स कर करवाया जाने हेतु महानरेगा की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करवाया गया है।

वितीय प्रगति

परियोजना हेतु वर्ष वार बजट आवंटन एवं किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

(रूपये लाखों में)

क्रम संख्या	वर्ष	बजट प्रावधान	संशोधित प्रावधान	व्यय राशि		
				परियोजना कोष	एस.आर.टी.टी.	कुल
1	08-09	0.50	0.50	2.42	-	2.42
2	09-10	839.00	690.00	668.40	20.00	688.40
3	10-11	1400.00	850.00	726.00	20.93	747.19
	कुल	**2239.50**	**1540.50**	**1397.08**	**40.93**	**1438.01**